Unorganized farm labourers

†*627. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state the action taken to protect interests of the unorganized farm labourers?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI SHARAD YADAV): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

To protect the interests of workers including unorganized agricultural workers, the Government has enacted the Minimum Wages Act, 1948, the Equal Remuneration Act, 1976, the Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 and the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979. A social security scheme namely, 'Krishi Shramik Samajik Suraksha Yojana-2000' has also been launched in selected 50 districts in the country with the objective of covering 10 lakh agricultural workers over a period of three years. The scheme envisages to provide through Life Insurance Corporation of India, life-cum-accident insurance, money-back, pension and superannuation benefits. Jan Shri Bima Yojana is also in operation for those below the poverty line or marginally above the poverty line which *inter-alia* includes agricultural labourers. Some other schemes for the welfare of rural workers including agricultural workers are Pradhan Mantri Gramodaya Yojana Swarnjayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), Jawahar Gram Samridhi Yojana (JGSY), Employment Assurance Scheme (EAS), National Social Assistance Programme (NSAP) etc.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: Sir, part (a) of my first supplementary is, whether the Government is considering rationalisation of the labour laws for ensuring a minimum level of protection of the workers, especially those who are working in the unorganized sector; if so, the details thereof. Part (b) is, whether the Government proposes to set up an independent regulatory authority

†Starred question Nos. 621, 623 and 627 were taken together.

for unskilled labourers and provide them training in various skills, to improve their socio-economic status, and also to ensure social security to the workers in the unorganised sector.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, वह मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। इस सदन में इस पर घंटों बहस हुई है और जो बातें आपने कहीं हैं, उन सब बातों का मैं जवाब दे चुका हूं लेकिन जो प्रश्न अंब आप पूछ रहे हैं, यह मध्य प्रदेश से संबंध रखता है मध्य प्रदेश में इंस्टीटयूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की एक संस्था है जहां एक टास्क फोर्स श्रीमती झाबावाला की अध्यक्षता में बना हुआ है। उसे मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है लेकिन माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर इस प्रश्न के दायरे में नहीं आता है।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Sir, it is not relating to Madhya Pradesh alone. The workshop was held there, but that relates to the entire country. We cannot confine it only to Madhya Pradesh.

SHRI K. KALAVENKATA RAO: This workshop was on "The Unorganised Sector". It is related to the main question. Sir, my second supplementary is, whether the Government proposes to formulate a national policy to provide health facilities and environmental safety to the workers in the unorganised sector as a welfare measure; if so, the steps initiated in this regard.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मध्य प्रदेश सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है और वह श्रीमती झाबावाला की अध्यक्षता में काम कर रहा है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI K. KALAVENKATA RAO: This question does not relate to the workers of Madhya Pradesh alone. It relates to the workers of the entire country.

SHRI SURESH PACHOURI: The Minister is from Madhya Pradesh, that is why he is giving stress to Madhya Pradesh.

SHRI SANJAY NIRUPAM: But he is not the Labour Minister of Madhya Pradesh. ...*(Interruptions)*...

श्री शरद यादव: सभापति जी, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं जो बात कर रहा हूं वह इस क्वेश्चन के दायरे में कह रहा हूं, इस सदन में दस घंटे इस पर बहस हुई है। यदि इससे संबंधित सवाल होता तो मैं जवाब देता। फिर भी जो प्रश्न इन्होंने पूछा है, उसका

जवाब मैं दे रहा हूं कि वहां एक टास्क फोर्स बना है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है। उसकी एक वर्कशॉप हुई जिसका उद्घाटन पी॰ के॰ अलग साहब ने किया और समापन मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने किया। उस टास्क फोर्स की रिपोर्ट अभी तक सरकार के पास नहीं आई है। हमने इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है। माननीय सदस्य जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के बारे में पूछ रहे हैं, वह निश्चित तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस संबंध में जो भारत सरकार है, हमारा मंत्रालय है, वह अनऑर्गेनाइज्ड लेबर को किस प्रकार सोशल प्रोटेक्शन दें, इस पर विस्तार से इस सदन में चर्चा हो चुकी है। हमारा मंत्रालय इस संबंध में पांच-छः मीटिंग्ज कर चुका है और इसका प्रश्न जब आएगा तो मैं उसका विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन यहां जो सवाल पूछा गया है, वह सिर्फ मध्य प्रदेश में जो टास्क फोर्स बनी है, उस पर जो वर्कशॉप हुई है, उसकी रिपोर्ट अभी तक सुबाई सरकार को नहीं मिली है। जब सुबाई सरकार को रिपोर्ट मिलेगी तब इस मामले में देश में जहां भी नेशनल कंसेसस बनेगा, उस पर विचार करने का काम होगा अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के मामले में खासकर पिछले पचास वर्षों में कई मीटिंगें हुई हैं, लेबर कांफ्रेंसस हुई हैं, आपके लेबर सेक्रेट्री भी बुलाए गए लेकिन इस मामले पर एक आम राय सभी सूबों में नहीं बन पा रही है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच नहीं बन पा रही है। निश्चित रूप से यह सवाल देश के सबसे लाचार और बेबस लोगों से वास्ता रखता है। इस मामले में कैसे कानून द्वारा उनकी रक्षा की जाए सुरक्षा की जाए। नेशनल कंसेसस कैसे बने, इस मामले पर बहुत सालों से बहुत बहसें और जिरहें चली है। इस संबंध में सन् 75 में और ज्यादा प्रयास हुए लेकिन सुबाई सरकारें इस मामले में एकमत नहीं हैं। सरकार अपने प्रयास में लगी हुई हैं। मै आपसे और माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि इस मामले में जब से श्रम मंत्रालय मेरे पास आया है तब से मैं अकेले इसी काम में लगा हुआ हूं। जिसमें इसी काम में चौबीस घंटे लगा रहता हूं कि कैसे इस मामले को सुलझाया जाए। पूरे अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में, जैसे सोशल सिक्योरिटी हैं, उन्हें जो सुविधाएं मिली हैं, चाहे विदेश के मामले में हो या किसी और मामले में हो वह जमीन पर एक नहीं हैं, और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज नहीं हैं लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सवाल मध्य प्रदेश सरकार से वास्ता रखता है और मध्य प्रदेश सरकार के पास अभी तक जो टास्क फोर्स बनी है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है और न ही उस पर कोई विचार हुआ है।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, according to the reply given by the hon. Minister, the Krishi Shramik Samajik Yojana, 2001, has been launched in selected 50 districts in the country, with an objective of covering 10 lakh agricultural workers over a period of three years. Andhra Pradesh is also covered by the Scheme. I would like to know how many people are benefited under this Scheme.

श्री शरद यादव: सभापति जी, साधारणतया श्रम सुरक्षा योजना में तकरीबन एक लाख लोग हिन्दुस्तान भर के पचास डिस्ट्रिक्ट में है और पचास डिस्ट्रिक्ट के पचास ब्लाक्स में हैं। अभी तक इसमें एक लाख वर्कर्स एनरोल कर लिए गए हैं। यह एक अच्छी स्कीम है और हिन्दुस्तान का जो अनऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चरल लेबर है उसके लिए इस स्कीम से एक छोटा-सा ठोस कदम उठा है। इसके नतीजे उत्साहवर्द्धक आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विषय में मुझे मालूम नहीं है कि कौन-से डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन में माननीय सदस्या को बता दूंगा कि यह कौन-से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन-से ब्लाक में है।

MISS MABEL REBELLO: Question No. 623.

श्री शरद यादव: एम्प्लोएमेंट के बारे में जो सवाल पूछा गया है, इसमें पिछले तीन साल में ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में 0.5 परसेंट, लगभग डेढ़ लाख लोगों के रोजगार घटे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में 0.98 रोजगार बढ़े हैं। निश्चित तौर पर इसके बारे में सरकार ने, गवर्नमेंट की इंप्लायमेंट जनरेशन जो स्ट्रेटजी है उसमें सेल्फ इंप्लायमेंट तथा वेज इंप्लायमेंट को बढ़ावा देना है। लेबर इन्टेंसिव सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इंप्लायमेंट जनरेशन करना है और स्किल्ड लेबर फोर्स को बढ़ावा देना है। यह हमारी स्ट्रेटेजी है। निश्चित तौर पर जो हमने कहा था एक करोड़ लोगों को जॉब देनी है, उसके बारे में हमारे मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों से कई तरह की योजनाएं हैं, चाहे वे रोड की हैं चाहे वे कंस्ट्रक्शन की हैं। और कई तरह की योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है, विचार ही नहीं कर रही है बल्कि उनमें एलोकेशन हुआ है और निश्चित तौर पर जो हमने कहा था उस काम में उस बात में हम प्रयासरत हैं और निश्चित तौर पर अभी तक नहीं हो पाया है आगे के समय में इसमें नतीजे अच्छे आएंगे।

MISS MABEL REBELLO: Sir, I had put my question in three parts, *i.e.* (a), (b) and (c). But the answer is totally incomplete.The Minister in his reply says, "The rate of growth of employment in the organised and unorganised sectors for major States and at the national level is given in the Annexure." But there was no Annexure. Just now I have got the Annexure. I wanted to have the statistics of three years. But the Minister has given the statistics for the years 1998, 1999 and 2000. The statistics for the year 2001 are missing. Then part (b) of my question has not been answered at all. In response to part (c) of my question he has given a general reply. He has not given a specific reply. In para 3 of his reply he says, "Particular attention would be paid to the policy environment influencing a wide range of economic activities which have a large employment potential." There is nothing specific. What are those economic activities which he has

mentioned? How is he planning to generate employment? In part (b) of my question, I specifically asked, "whether it is a fact that 50 lakh jobs have been lost in the organised and unorganised sectors?" These are authentic figures. In the organised sector, we have lost 4.5 lakh jobs by way of VRS, closing down of industries, etc. In the unorganised sector we have lost 45 lakh jobs. When this Government came to power, in their manifesto, the Government said that they would create one crore jobs annually. Instead of creating one crore jobs annually, they are losing 50 lakh jobs annually. What is the Minister saying? The answer given by the Minister is not at all satisfactory. I want complete answer from the Minister. When the question is in three parts, the answer should also be in three parts. He has given a general reply. He is not giving any specific reply, Sir, I want specific replies to my specific queries.

श्री शरद यादव: सभापति जी, जो सवाल ''ए'' है, ''बी'' है तो ''बी'' में जो सवाल पूछा गया है ....(**व्यवधान**)....

कुमारी मैबल रिबैलो: यहां कुछ भी नहीं दिया है। ''ए, बी, सी'' कहां है?

श्री संघ प्रिय गौतम: जवाब देने दीजिए, जवाब सुन लें।

श्री शरद यादव: जो ''बी'' का है उसका भी जवाब मैंने दिया है ....(**व्यवधान**)....

कुमारी मैबल रिबैलो: मैं लाकर दे दूं आपको? क्या यह ''ए, बी, सी'' है?

श्री संघ प्रिय गौतम: जवाब तो सुन लें। कुछ कहने तो दें।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, मैंने ''बी'' का भी जवाब दिया है कि जो हमारे पास आंकड़े हैं, या जो फिगर्स हैं, जो सर्वे है, उनमें 1.5 लाख जॉब्स कम हुए हैं। मैं आपके माध्यम से सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यह फिगर ज्यादा हो सकता है, मैं यह नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो अवेलेबल हैं, जो सर्वे हुए हैं, उससे मैंने उनको बताया है। निश्चित तौर पर जो जॉब क्रीएशन की बात है हम एक करोड़ जॉब्स कैसे बनाएं ....(**व्यवधान**)....

कुमारी मैबल रिबैलो: सर, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। इसका स्पेसिफिक रिप्लाई दीजिए।

श्री शरद यादव: स्पेसिफिक ही दे रहा हूं। I am answering specifically. सभापति जी, इंप्लायमेंट जनरेशन के बारे में मैंने कहा कि सरकार इस पर गंभीर है और सरकार यह मानती है कि आर्गेनाइज्ड सेक्टर में जॉब्स कम हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आंकड़े की बात मैं नहीं करता कि आंकड़े ....(**व्यवधान**).... हमारे ठीक हैं या आपके ठीक हैं ...(**व्यवधान**)...

कुमारी मैबल रिबैलो: मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है, उसका स्पेसिफिक रिप्लाई दीजिए। आप again जनरल बात कर रहे हैं, सरकार गंभीर है। इसका क्या मतलब है? मैंने आंकड़े पूछे है। आप मुझे स्टेटिसटिक्स दे दीजिए। सब्सटैंशएट कीजिए वह स्टेटिसटिक्स।

श्री शरद यादव: यानी एक लाख 50 हजार जॉब कम हुए। यह मैंने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया है ....(**व्यवधान**)....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, the question was whether 50 lakh jobs have been lost in 2001-02 or not; the Minister is mentioning about 1999-2000. He should say whether the hon. Member is correct or not, Let him correct her, if she is wrong. इसका फिगर आपने दिया नहीं। मेरे ख्याल से, सभापति जी, इसके लिए झगड़ा नहीं करके, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर मंत्री जी चाहें तो वह फिर से आएं और अगले हफ्ते इसका जवाब ठीक तरह से लायें तथा इसके बारे में चर्चा करें और 2001-02 में 50 लाख जॉब्स लॉस्ट। It is a very serious charge. आपके मंत्रालय ने प्रश्न मिलने के बाद भी आपको यह रिप्लायी दिया। यह आपकी गलती नहीं है। आपके मंत्रालय ने सोचा ....(**व्यवधान**). सर, इसमें कहा है ....(**व्यवधान**).

श्री शरद यादव: सभापति जी, यह जो बात कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है .... (**व्यवधान**).

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Kindly go through the reply. Sir, Why should we put questions in (a), (b) and (c) parts, if the reply is going to be a general one?

श्री शरद यादव: यह जो बात कह रहे हैं, यह ठीक नहीं है ....(**व्यवधान**).

MR. CHAIRMAN: Let him speak ....(*Interruptions*).

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप भी इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं ....(**व्यवधान**).

श्री शरद यादव: मैं तैयार ही हूं ....(**व्यवधान**).

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, गौतम जी, आप मैंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप क्वश्चन का ''सी'' पार्ट देखिए और उत्तर भी देख लीजिए। .... (**व्यवधान**).

श्री शरद यादव: माननीय सभापति जी, मैंने कहा कि इस मामले में डिस्प्यूट है और जो भी आंकड़े मुझे मिले हैं मैं निश्चित तौर पर उनसे संतुष्ट नहीं हूं यानी हमारे हिसाब से जो आपने पिछले तीन साल का बोला है उसमें एक लाख पचास हजार ....(**व्यवधान**).

श्री दीपांकर मुखर्जी: पिछले साल 50 लाख यानी 2001-02 में 50 लाख जॉब समाप्त हुए हैं या नहीं, यह क्वश्चन है और यह बहुत सीरियस क्वश्चन है।

श्री शरद यादव: सभापति जी, यह सवाल मैंने अपने मंत्रालय से पूछा है कि जो एक साल दिया गया है इसका भी मुझको बता दें और वह जब मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको दे दूंगा। पिछले तीन साल का मैं दे रहा हूं, लेकिन स्पेसेफिक सवाल जो पूछा है वह आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, मैं उनको आपके पास भेज दूंगा। ....(**व्यवधान**).

कुमारी मैबल रिबैलो: आप क्या कह रहे हैं ....(**व्यवधान**).

श्री दीपांकर मुखर्जी: बड़ा सीरियस क्वश्चन है।

MR. CHAIRMAN: Let him reply ...(*Interruptions*). Please hear the Minister ...(*Interruptions*).

कुमारी मैबल रिबैलो: स्पेसेफिक क्वश्चन का स्पेसेफिक रिप्लायी देना होगा, आफ्टरआल रिप्लायी चाहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम: सर, दो-दो सदस्य एक साथ सवाल पूछ रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Let him reply ....(*Interruptions*). Please hear the Minister ....(*Interruptions*).

श्री शरद यादव: सभापति जी, इस पर मैंने आपके माध्यम से बता दिया है कि जो स्पेसेफिक ''बी'' पार्ट वाला सवाल है, इसके बारे में आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम आंकड़े उपलब्ध करके आपको बताने का काम करेंगे। अब जो रोज़गार पैदा किए जा रहे हैं जो 2001-02 में रूरल डिवेलपमेंट में 8080 करोड़ रुपए अलाट किए गए हैं, प्रधान मंत्री संपूर्ण रोजगार योजना में 4989 करोड़ रुपये 2001-02 में अलाट किए गए, प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में 2375 करोड़ का प्रावधान किया गया है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना में 815 करोड़ अलाट किए गए हैं, वेस्ट लैंड डिवेलपमेंट में 2000-01 में 900 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह जो नेशनल हाईवे डिवेलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें 94 हजार करोड़ रुपये आने वाले 2007 तक खर्च करने हैं। इतना पैसा इसमें अलाट किया गया है। रोड लिंकिंग में 4000 करोड़ सन् 2000 से लेकर 2007 तक खर्च किए जायेंगे, रोड सेफ्टी पर 17 करोड़ खर्च किए जायेंगे, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पर 1991-92 में 293 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में 2002 से लेकर आगे आने वाले समय में 1250 करोड़ खर्च किए जायेंगे। और एम्प्लायमेंट जनरेशन प्रोग्राम पर के०वी०आई०सी० के अंतर्गत 2001-02 में 120 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सभापति जी, सरकार ने ये सारा एलोकेशन इन सारी मदों पर किया है। अब चाहे वह रोड कंस्ट्रक्शन हो

या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, ये सारे प्रोग्राम प्रधान मंत्री सड़क रोजगार योजना के अंतर्गत आते हैं और ये खासकर रोजगार को पैदा करने वाले और बढ़ाने वाले प्रोग्राम हैं। यह सरकार की योजना है जिसे मैंने मोटे-मोटे तौर पर आप के सामने रखा है।

MR. CHAIRMAN: Mr. B.P. Singhal.

MISS MABEL REBELLO: Sir, I want to...

MR. CHAIRMAN: No. no. When the questions are clubbed together, only the first supplementary is allowed.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, I have never been able to comprehend how the figures pertaining to the unorganised sector are calculated and published very authentically in various magazines and other publications. For instance, take the case of migrant labour, the labour that does work at brick kilns, which are seasonal, or the sugarance labour. How do you calculate them? Or how are they calculated. If all this calculation is being done through the Employment Exchange, then I want to put a question to the hon. Minister. There are thousands of Employment Exchanges; every district has an Employment Exchange. Has the Labour Ministry computerised them all, because I know of a case where one person is registered in, at least, half-a-dozen Employment Exchanges? So, if all the common names are removed from the Employment Exchanges, perhaps, we may get a more accurate figure. Has any exercise been undertaken to remove the common names from the Employment Exchanges all over the country? And, what is the methodology of calculation?

श्री शरद यादव: सभापति जी, इस के लिए एक ही जरिया है और वह एम्प्लायमेंट एक्सचेंज जोकि सूबाई सरकारों के हाथों में है। हम इस के आंकड़े उन से ही कलेक्ट करते हैं और वही आंकड़े हम जवाब में देते हैं। अब जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा इन में बहुत से कॉमन नेम्स भी होते हैं, जिन्हें छांटने का काम मुश्किल होता है। दरअसल हम तो एन॰एस॰एस॰ओ॰आई॰ द्वारा किए गए सर्वे के आंकड़े देते हैं।

SHRI CHO. S. RAMASWAMY: When we speak of the unorganised sector, I think we also speak of many self-employed persons working on the streets and platforms. They have either small eateries or they do ironing of clothes or they have teashops. They sell so many sundry items like toys and other things. In the names of cleaning the cities, in the name of hygiene, many Governments

are doing away with these self-employed persons. This is a huge problem in every city because all those persons are removed from the platforms, both on the ground of ageing and for purposes of smooth traffic. Should not the Government have some scheme, some plan, to reconcile the two interests, one, of an honest livelihood for these persons who do not break the law and, on the other, of hygiene, traffic and needs of modern living. Unless a scheme is drawn to reconcile these two interests, we will be converting all these honest persons into anti-social elements and petty thieves. Has the Government got any scheme to get these two interests reconciled?

श्री शरद यादव: सर, माननीय सदस्य की जो कनसर्न है, उस के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति और सहमति है। सभापति जी, निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी समस्या हिंदुस्तान में है जिस में एक बड़ी संख्या रेहड़ी वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगे वाले, छोटी दुकान चलाने वाले और मूंगफली बेचने वालों की आती है और शहरों में इन को बड़े पैमाने पर हटाया जाता है। लेकिन सवाल सीधा सूबाई सरकार से जुड़ा होता है, केन्द्रीय सरकार के हाथ में यह काम नहीं है। निश्चित तौर पर माननीय सदस्य अलग-अलग सूबो से आते हैं और वहां भी इस तरह के रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, तांगे वाले और दूसरे अन-अर्गनाइज्ड वर्कर्स हैं, लेकिन इन सब के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सरकारें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बंगाल की सरकार अच्छे काम कर रही हैं और इनके लिए अच्छे लेजिस्लेशन भी ला रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी दिक्कत आ रही है। यह जो सवाल है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, एक बड़ी समस्या है। हिन्दुस्तान में जो भी बेरोजगार होता है वह या तो पान का पटरा लगाने लगता है या कहीं मोची का काम करने लगता है। मैं निश्चित तौर पर यह मानता हूं कि इस मामले पर पूरे देश भर में एक कंसेंसस बनकर सामने आए कि कैसे इनको प्रोटेक्शन दिया जाए, कैसे इनको ठीक किया जाए। कंस्ट्रक्शन लेबर के बारे में अभी दोनों सदनों में एक कानून पास किया गया। मैंने सूबाई सरकारों और सबसे कहा, मगर एक दो सूबाई सरकारों ने इंपलीमेंट किया, बाकी सरकारों ने नहीं किया। ये कंस्ट्रक्शन वर्कर भी ऐसे ही लोगों में आते हैं। तो यह एक बड़ा सवाल है और इस सवाल पर जो माननीय सदस्य ने कहा, मैं मानता हूं कि काफी बड़ी दिक्कत है, जो अच्छे लोग हैं वह ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, किन्तु हिन्दुस्तान में आबादी बढ़ने से, शहरों का विस्तार होने से गांवों में रोजगार के अवसर कम होने से बड़े पैमाने पर लोग गांवों से उजड़ कर शहरों में आते हैं और वह लोग किसी तरह से बाजारों में सड़क के किनारे अपनी रेहड़ी लगाकर काम करते हैं या एक तरफ बैठक जूते सुधारने का काम करते हैं या कई तरह की मशीनें सुधारने का काम करते हैं या फिर साइकल की पंचर

बनाने का काम करते हैं। अब इनको कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए, कैसे इनको प्रोटेक्शन दी जाए, यह एक बड़ा सवाल है।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं एक तो इनका जवाब तर्कसंगत नहीं है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि संगठित क्षेत्र में एक लाख पचास हजार रोजगार के अवसर घटे हैं और असंगठित क्षेत्र की जो इन्होंने बात कही कि वह तांगेवाले, रिक्शे वाले, मोटर वाले या जिनकी बात कही, मैं सोचता हूं कि इस प्रश्न का उससे कोई संबंध नहीं है। मैं स्पेसिफिक उनसे पूछना चाहता हूं, यह पार्ट 'सी' में जो है — the manner in which the Government propose to address the problem of educated unemployed. अगर माननीय मंत्री जी का जवाब देखें तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है — अत्यधिक रोजगार संभावना वाली आर्थिक गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करने वाले नीतिगत वातावरण पर विशेष बल दिया जाएगा। तो जो देश में बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए यह माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है। मैं सोचता हूं कि मंत्री जी पूरी तैयारी से नहीं आए हैं और दूसरा जिस प्रकार का इन्होंने जवाब दिया है, दसवीं योजना के बारे में जो उल्लेख किया है, मैं चाहूंगा, सभापति जी, कि इस प्रश्न पर सही ढंग से स्पष्ट उत्तर आने के लिए इसे किसी दूसरे दिन के लिए रखा जाए ताकि मंत्री जी पूरी तैयारी के साथ सदन में आएं और सदन को सही जानकारी देने की कृपा करें।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैं वोरा जी को बताना चाहूंगा कि जब इस सदन में लेबर मिनिस्टरी पर डिबेट चली थी तो एक लंबी डिबेट चली थी, विस्तार से डिबेट चली थी। माननीय सदस्य ने जो पूछा था, निश्चित तौर पर मैं उस पर बोल रहा था।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, प्रश्न संख्या 623 भी इसके साथ लिया जा रहा है।

श्री शरद यादव: मैं कहां एतराज कर रहा हूं।

श्री मोती लाल वोरा: माननीय सभापति जी, प्रश्न संख्या 623 के पार्ट सी के बारे में मैंने पूछा है।

श्री शरद यादव: माननीय सभापति जी, अगर वोरा जी मेरी बात सुन लेंगे तो जरूर उनकी समझ मे आ जाएगा। मेरी विनती यह है कि जो सवाल यहां पूछा जा रहा था। जो माननीय सदस्य रामास्वामी जी ने पूछा था, उसके बारे में मैं बोल रहा था। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया था कि हिन्दुस्तान के गांवों से उजड़ कर बेरोजगार होकर लोग बड़े पैमाने पर शहरों में आ रहे हैं और वह लोग शहरों में आकर रोजगार के लिए रास्तों पर, किनारों पर

बैठते हैं, उस सवाल का इस से वास्ता नहीं है, तब भी मैंने उनका जवाब देने का काम किया कि इस संबंध में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकारें अच्छा काम कर रही है। जो आपने पार्ट 'सी' के मामले में सवाल पूछा है, तो इस मामले में एक अहलुवालिया कमेटी बनी थी, उसने जो रिकमंडेशन दी थीं, उन पर विवाद हो गया और अब प्लानिंग कमीशन ने एक एस॰ डी॰ गुप्ता कमेटी बनाई है इसमें सबसे बड़ा स्ट्रेस यही है कि कैसे एंपलायमेंट जनरेट किया जाए। उस कमेटी ने जितनी रिकमंडेशन दी थीं, वह सारी रिकमंडेशन एस॰ डी॰ गुप्ता कमेटी को दे दी गई हैं। कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, कैसे जो एंपलायमेंट का फिगर गिर रहा है उसको रोका जाए, आर्गेनाइज्ड सैक्टर और अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, इसके बावत हमारे जो लेबर सेक्रेटरी हैं उनकी चेयरमेनशिप में भी एक कमेटी बनी है। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सब्मिट कर दी है और निश्चित तौर पर उसका प्रपोजल आने वाला है। हिन्दुस्तान में जो अनएम्प्लायमेंट है, इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हमारे पास आई॰टी॰आई॰ बहुत कम है। पूरे देश भर में आई॰टी॰आई॰ के बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो हमारे पास 75 तो सैंट्रल इंस्टिट्यूट हैं, 4500 के करीब आई॰टी॰आई॰ प्राइवेट सैक्टर में हैं या उन्हें स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और हिन्दुस्तान में स्किल लेबर दुनियाभर में सबसे कम है। हमारी कोशिश है कि आई॰टी॰आई॰ का विस्तार किया जाए। बहुत से लोग आई॰टी॰आई॰ नहीं जाते हैं, अपने तरीके से अपना काम सीख लेते हैं — मिस्त्रीगिरी का काम सीख लेते हैं, और कोई स्किल्ड वर्क सीख लेते हैं, मशीन सुधारने का काम सीख लेते हैं। तो जो स्किल उन्होंने हासिल किया है, उसके आधार पर बाजार में उनको किसी तरह से अवसर मिल सके, ऐसा प्रयास भी हमारा चल रहा है और आने वाले समय में इसके लिए एक बड़ा पैसा ऐलोकेट करने के लिए प्लानिंग कमीशन से हमने आग्रह किया है। इस तरह से सरकार प्रयास कर रही है ताकि जो अनएम्पलायड् यूथ है, चाहे वह शिक्षित है या अशिक्षित है, उसको काम मिल सके।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह: महोदय, प्रश्न संख्या 623 के तीसरे भाग में कहा गया है "the manner in which Government propose to address the problem of educated unemployed," इस बारे में मंत्री जी का जवाब भी है और आकलन दिया गया है कि किस विभाग में समस्या का निदान कैसे हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि जवाब पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो मैं सरकार से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जानना चाहता हूं कि इस जाईगेंटिक प्राब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सरकारी रास्ते बनाए गए हैं, सरकार क्या उन्हीं पर कार्य करेगी या सेल्फ एम्प्लायमेंट पर भी जोर दिया जाएगा? मेरे विचार में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज्यादा जोर देने से इसका निदान हो सकता है। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या राज्य सरकारों की, उसके विभिन्न विभागों या संस्थाओं की कोई बैठक बुलाई जाएगी? श्रम मंत्रियों की

बैठक होती रहती है, श्रम सचिवों की भी बैठक होती रहती है, मैं जानना चाहता हूं कि इस समस्या से निबटने के लिए क्या सरकार के विभिन्न विभागों से या सरकारी संस्थाओं से मिल-जुलकर कोई उपाय किया जाएगा क्योंकि जिस ढंग का प्राब्लम पैदा हो रहा है उसमें अनआरगेनाइज्ड सैक्टर और आरगेनाइज्ड सैक्टर में इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि वह इस वास्ट अनएम्प्लायमेंट का सामना कर सके? इसलिए मैं मंत्री जी से यह स्पेसिफिक जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की यह इंटेंशन है या क्या सरकार की ऐसी योजना है कि सेल्फ एम्प्लायमेंट स्कीम को बड़े पैमाने पर जनरेट करके वह इस जाइगेंटिक प्राब्लम का मुकाबला कर सके?

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य ने सही कहा है, सरकार सबसे ज्यादा प्रयास कर रही है कि सेल्फ एम्प्लायमेंट ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किया जाए और इस मामले में सरकार चिंतित भी है, प्रयासरत भी है। आज ही शाम पूरे देश से लेबर मिनिस्टर और लेबर सैक्रेटरीज़ मैंने बुलाए हैं, और कल उनके साथ मेरी मीटिंग है और इन सारे सवालों पर, जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, जो बड़े कठिन सवाल हैं और कठिन प्रयासों से ही इनका समाधान हो सकता है, विचार किया जाएगा। यह प्रयास तभी सफल हो सकता है जब सूबाई सरकारों की भी इस पर सहमति हो जाए।

श्री मोतीलाल वोरा: मेरा कहना है कि राज्यों के जो श्रम मंत्री हैं, आप उनकी इसी सत्र के दौरान एक बैठक बुला लें ताकि आपको सही ढंग से तथा पूरी जानकारी मिल सके और राज्यों में क्या हो रहा है, उसका भी आपको पता चल सके। इसलिए मेरा सुझाव है कि राज्यों के श्रम मंत्रियों की एक बैठक आप शीघ्रातिशीघ्र बुलाएं ताकि हर राज्य की स्थिति की जानकारी आपको हो सके।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैंने अभी कहा कि कल ही मैंने बैठक बुलाई है, वोरा जी को शायद पता नहीं है या यह सुन नहीं सके, मैंने कल ही बैठक बुलाई है और यह मीटिंग इस देश में पिछले 50 सालों से लगातार चल रही है। हमारे ज़माने में ...(व्यवधान)....

श्री मोतीलाल वोरा: आप बहुत विद्वान आदमी हैं, श्रम नीति के बारे में आपको पूरी जानकारी है और आप काफी अनुभवी हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने लाल किले से जो घोषणा की थी हम एक करोड़ लोगों को रोज़गार के अवसर देंगे, मैं जानना चाहता हूं कि उन एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा का क्या हुआ?

श्री शरद यादव: वोरा जी, मैंने इसके बारे में बताया है। निश्चित तौर पर हमें सैल्फ इम्प्लॉयमेंट तथा वेज इम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है। यह विचाराधीन है और हम इस पर काम कर रहे हैं।

DR. T. SUBBARAMI REDDI: Mr. Chairman, Sir, I would like to point out that there has been a slowdown in the employment in the public sector. It was 1.52 per cent per annum in the years between 1983 and 1994. But now a negative growth which started between 1994 and 2000, has gone to .03 per cent. So, I would like to know from the hon. Minister how this negative growth has started. This is part one of my question. The second part is, as just now we have heard, the hon. Prime Minister had promised in 2000 in his Independence Day Speech on 15th August that one crore jobs would be created. In his speech next year, he did not at all touch this point. Sir, part (c) of the main question about the manner in which the Government proposes to address the problem of educated unemployment has not been answered. The answer has not come so far. हम सोचेंगे, हम इस पर काम कर रहे हैं, that is not correct. I would like to know from the hon. Minister what has been the progress till today—not a meeting today or tomorrow. Secondly, there are so many schemes funded by the Central Government to create self-employment. I would like to know what efforts have been made to create self-employment's immediately, through the funds available under the Central Government's Self-employment Scheme. What steps have been taken by the Government to solve the problem of educated unemployment? As you know, there is a lot of frustration among the educated youth because there is no job for them. As a result, they are going on a wrong track. This is the most burning problem of the country. मीटिंग्ज़ करने से कुछ नहीं होता है। Therefore, I would like to have a categorical assurance from the Hon. Minister to this House as to how they are going to solve this problem and in what way they are going to make progress in this regard. ....(*Interruptions*)....

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैं इन बातों का जवाब दे चुका हूं। यह जो एक करोड़ लोगों को रोज़गार देने का सवाल है, इसके बारे में मैंने बताया है कि कहां-कहां कितनी-कितनी धनराशि का ऐलोकेशन किया गया है। प्रधान मंत्री जी ने जो एक करोड़ लोगों के लिए रोज़गार के सृजन की बात कही है, इस धनराशि से आने वाले समय में उससे अधिक रोज़गार का सृजन होगा। महोदय, शिक्षित बेरोजगार युवकों के बारे में मैंने कहा कि जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए शिक्षा की योजना को इस तरह बनाना पड़ेगा कि बड़े पैमाने पर स्किल्ड लेबर तैयार हो सके। इसके बारे में मैंने सदन को बताया है। आगे की योजना के लिए एस॰ पी॰ गुप्ता ....(व्यवधान)....

सभापति महोदय, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण बात है। जब मैंने साफ-साफ आंकड़े देकर बताया है कि रोजगार कैसे पैदा होगा, मैंने धनराशि का ऐलोकेशन भी बताया है, उसके बाद भी माननीय सदस्या बार-बार खड़ी हो रही है ....(**व्यवधान**)

कुमारी मैबल रिबैलो: आपने क्वश्चन का कोई स्पैसिफिक जवाब नहीं दिया है ....(**व्यवधान**)

श्री सभापति: हो गया ....(**व्यवधान**)

श्रीमती सरोज दुबे: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के युग में सबसे ज्यादा रोजगार का नुकसान महिलाओं का हो रहा है क्योंकि ज्यादातर महिलाएं अकुशल हैं। जब तक मशीनीकरण नहीं हुआ था, तब तक उनको काम मिल जाता है और वे अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकने में समर्थ थीं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि इस उदारीकरण के कारण जो शिक्षित और अशिक्षित महिलाएं बेरोजगार हो रही हैं उनके हित के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए आप वैश्वीकरण के कौन से कदम उठाने जा रहे हैं? इन बेरोजगार महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं।

श्री शरद यादव: महोदय, जो पहला सवाल था, उसमें मध्य प्रदेश में जो टास्क फोर्स बना है, उसके बारे में पूछा गया था। जो ग्लोबलाइजेशन की नयी रेजीम आई है, उसके चलते हमारे मंत्रालय पर इसका कितना असर होने वाला है, इसकी एक स्टडी चल रही है। सेकेंड लेबर कमीशन हमने बनाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी जल्दी ही आने वाली है। सरोज जी ने जो बात पूछी है, उस रिपोर्ट से पता चलेगा कि ग्लोबलाइजेशन की रेजीम के चलते महिलाओं के रोजगार पर और अन्य मजदूरों के रोजगार पर कितना असर पड़ेगा।

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, the hon. Minister has mentioned in his reply that particular attention would be paid to the policy environment influencing a wide range of economic activities which have a large employment potential. So, I would like to know from the hon. Minister whether—after the report of the 21st Workshop on Unorganised Labour Sector—there is any proposal to formulate a scheme for payment of Provident Fund; and whether there is any insurance scheme for all types of unorganised workers who constitute 90 per cent of the workers in the country.

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, जो पहला सवाल था उसमें माननीय सदस्या जो पूछ रही हैं, वह टर्म्स आफ रिफ्रेंस में नहीं है। उसके टर्म्स आफ रिफ्रेंस में, एग्रीकल्चर में, फॉरिस्ट में, शहरों में, अन्य सैक्टरों में जो उनके लिए वेलफेयर फंड बनाए गए हैं तथा जो एक्सिटिंग वेलफेयर फंड हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट लेविल पर बोर्ड बनाकर के उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, मिनिमम वेजिज पर कैसे प्रोग्राम को बढ़ाया जाए, स्किल्ड अपग्रेडेशन कैसे किया जाए, माईग्रेंट लेबर के लिए क्या सुविधाएं दी जाएं ग्लोबलाइजेशन को देखते हुए क्या उसमें असर होने वाला है। यह मध्य प्रदेश की योजना है और वहां की टास्क फोर्स को यह काम दिया गया है।

SHRI MURLI DEORA: Sir, when the NDA came to power, they had made a programe, the National Agenda for Governance. Under the National Agenda for Governance, the main theme of the agenda was 'बेरोजगारी हटाओ', 'eradicate unemployment'. During the last two years, more than two million jobs have been lost, instead of giving 10 million jobs every year. Several hundreds and thousands of small-scale, medium-scale and public sector industries have been closed. I would like to know what has happened to the National Renewal Fund, which was created earlier. How much money, how much resources have been provided to the National Renewal Fund by the Government? How much of that has been disbursed? What is the future programme of the National Renewal Fund?

श्री शरद यादव: सभापति जी, इस सवाल में यह आता नहीं है। मैं इसका उत्तर माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

प्रो॰ रामगोपाल यादव: श्रीमन्, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे सवाल पूछने की इजाजत दी। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे जमाने में पहले बहुत मीटिंग हुई थी। अब भी आपका जमाना है और कल भी आपका जमाना है और कल भी मीटिंग करने जा रहे हैं। आप जितने सवालों का जवाब दे रहे हैं, स्पेसिफिक सवाल का जनरल जवाब दे रहे हैं। मैं अपने जनरल सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं।

मैं बेसिकली अध्यापक हूं और जब पर्चा आ गया तो उससे हटकर पूछूंगा। मेरा सवाल यह है कल जो मीटिंग आप करने जा रहे हैं, उस मीटिंग में आपकी क्या योजना है, कैसे लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे? क्या इसकी कोई स्पेसिफिक संख्या है कि इस वर्ष के अंत में इतने बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे? माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो

एक करोड़ की घोषणा की थी, वह तो आप नहीं बता पाए कि कितने लोगों को रोजगार दे पाए। फिर भी अगर आपके पास जानकारी हो कि कितने लोगों को रोजगार मिला है उसकी संख्या बताएं? जो कल योजना बनाने जा रहे हैं उसमें कितने लोगों को रोजगार देंगे?

श्री शरद यादव: रामगोपाल जी ने मेरी बात ठीक से सुना नहीं है जो मैंने जवाब दिया है। यानि हिन्दुस्तान में जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास जो स्किल्ड लेबर है शिक्षित और गैर शिक्षित लोगों में यह समस्या कम है। एक तो हमारी योजना यह है कि स्किल्ड वर्कर्स को कैसे और बड़े पैमाने पर तैयार किया जाए। हमने 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रपोज़ किया है कि 4700 करोड़ रुपये ऐलोकेट किये जाएं। निश्चित तौर पर आपने अनऑरग्नाइज्ड लेबर के बारे में जो कहा है — शिक्षित के बारे में लोगों ने पूछा, अब मैं अनऑरग्नाइज्ड सैक्टर के बारे में बता रहा हूं कि इस पर मैंने ऐलोकेट करके, नम्बर के साथ, बजट ऐलोकेशन बताया कि जब रोड बनेगी, मकान बनेंगे...

प्रो॰ रामगोपाल यादव: आपने पैसा ऐलोकेट किया है पर उसमें कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?

श्री शरद यादव: उस संबंध में काम चल रहा है।

प्रो॰ रामगोपाल यादव: कितने लोगों को काम मिलेगा?

श्री टी॰एन॰ चतुर्वेदी: वह सूचना लेबर मिनिस्टर देंगे।

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, यह जो मैंने ऐलोकेशन बताया, उस पर काम चल चुका है और लोगों को रोजगार मिले हुए हैं। मैंने कहा कि अनऑरग्नाइज्ड सैक्टर में जो रोजगार है, वह बढ़ा है, .98 परसेंट बढ़ा है जबकि ऑरग्नाइज्ड सैक्टर में घटा है।

श्री नीलोत्पल बसु: आप कल्पना से बता रहे हैं।

श्री शरद यादव: सभापति जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं उनकी जानकारी को चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

प्रो॰ रामगोपाल यादव: श्रीमन्, जो रोड्स वगैरह के बारे में मंत्री जी बता रहे हैं, अब स्थिति यह हो गयी है — माननीय सड़क मंत्री जी बैठे हुए हैं — लोग मशीनों से काम कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी मशीनें आ गयी हैं जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां सौ मजदूर काम करते थे, वहां एक मशीन 200 लोगों को बराबर काम कर रही है। इतने बड़े-बड़े व्हीकल्स और मशीनें आ गयी हैं कि एक दो किलोमीटर रोड बनाने के लिए भी मशीनें काम करती हैं और किसी को काम नहीं मिलता।

श्री शरद यादव: माननीय रामगोपाल जी, 30 करोड़ मैनडेज़ इस अकेले नेशनल हाईवे प्रोजैक्ट से लोगों को मिलेंगे और यह आंकड़े मैं आपको — जब इसका जवाब दे रहा था, तब जवाब नहीं दिया था — दूसरा जवाब मैं बता रहा हूं कि 30 करोड़ मैनडेज़ हैं। निश्चित तौर पर मैं आपकी बात मानता हूं कि...

प्रो॰ रामगोपाल यादव: बड़ी-बडी मशीनें आ रही हैं कहां मैनडेज़ मिल रहा है?

श्री शरद यादव: सभापति जी, मैं इनकी बात मानता हूं कि मशीनों के चलते रोजगार घटे हैं।

श्री संजय निरुपम: मशीनें चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN: Sir, my question is regarding the welfare schemes for the unorganised sector. There was a demand for bringing a comprehensive central legislation for the agricultural labour and we have during the last 20 years, held a number of discussions about this legislation. More than a dozen discussions between the State Labour Ministers, Labour Secretaries and the Central Government have already taken place during these two decades. But, so far, nothing fruitful has come out for the unorganized sector. The Government has announced only this Bima Programme, which also has failed in its implementation. You announced that one million agricultural labourers will be enrolled in this programme, but only a little more than five thousand labourers were enrolled. So, this programme has failed entirely. In such a situation, I would like to know whether the Government will come out with a comprehensive legislation for the agricultural labourers or not. And will the Government give an assurance in this House regarding the legislation? That is the first part of my question.

Sir, the second part of my supplementary is regarding the total mandays of employment, which is going down now-a-days. Does the Government have any idea regarding the number of mandays available for the agricultural labourers in our country? Will you give an assurance in this House regarding the legislation? And, will you give the details regarding the number of mandays available in the country?

श्री शरद यादव: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात ऐग्रीकल्चर लेबर के बारे में कही, वह शत प्रतिशत सही है। इतनी बार मीटिंग्स हो चुकीं, इतनी बार कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकीं लेकिन इस सवाल पर — हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, जिन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं जिनकी सबसे ज्यादा खाने और रहने की दिक्कत है, उनके बारे में पिछले दो डिकेड्स में कई कॉन्फ्रेंसिंग हुई, सब लोग बैठे, प्राइम मिनिस्टर भी हर मीटिंग में रहे लेकिन इस सवाल को हम आज तक हल नहीं कर पाए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह मामला सूबाई सरकारों के हाथ में है, और वे इस संबंध में सहमत नहीं होती, इस संबंध में जब भी लैजीस्लेशन बनाने का काम होता है — यह राज्यों की सभा है, आप लोग अपनी स्टेट गवर्नमेंट को कहिए, मैनडेट दीजिए कि ऐग्रीकल्चर लेबर के बारे में कानून बनाने के बारे में सहयोग दें। मैं सब सरकारों के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन इसमें कांन्सैंसस नहीं बन पाता, आम सहमति नहीं बन पाती।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप हां बोल दीजिए।

श्री शरद यादव: लेजीस्लेशन लाएंगे भी तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वह सूबाई सरकारें ही तो करेंगी।

श्री दीपांकर मुखर्जी: लेजीस्लेशन लाइए, इम्प्लीमेंट कराने का काम हमारा है।

श्री शरद यादव: सभापति जी, बहुत से कानून हैं, बहुत सा पैसा दिया हुआ है लेकिन वह पूरा सूबाई सरकारों के हाथों में नहीं जाता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप लेजिस्लेशन तो लाइए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, देश में जो ई॰एस॰आई॰ हॉस्पिटल्स हैं, उनको केन्द्रीय सरकार इतना पैसा देती हैं लेकिन उनकी हालत क्या है? कुछ सूबों में तो ठीक है लेकिन जिन्हें सूबाई सरकारें चला रही हैं, उनकी हालत क्या है? निश्चित तौर पर इसमें उनकी सहमति लेना जरूरी है। इसका इंप्लिमेंटेशन तभी हो सकता है जब सूबाई सरकारों को विश्वास में लिया जाए। यह राज्यों की सभा है और यहां राज्यों के लोग हैं, आप अपनी-अपनी राज्य सरकारों पर दबाव डालें और आम सहमति बने, तभी यह हो सकता है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप लेजिस्लेशन लाइए, उसके बाद हो जाएगा।